

दिव्यांगों को पैरों पर खड़ा होने में मददगार

संस्थान के 40 साल पूरे होने पर महानिदेशक डॉ.सुनील शुक्ला से बातचीत

# पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमिता की अलख जगाएगा ईडीआईआई



पत्रिका  
साक्षात्कार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क  
patrika.com

अहमदाबाद, गांधीनगर स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) 20 अप्रैल को अपनी स्थापना के 40 साल पूरे कर रहा है। इस बीच, संस्थान देश ही नहीं विदेशों में भी अपने पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उद्यमिता (एन्टरप्रेन्योरशिप) की अलख जगाने का काम कर रहा है। इसी अवसर पर पेश है संस्थान के महानिदेशक (डीजी) डॉ.सुनील शुक्ला से राजस्थान पत्रिका के

संवाददाता नगेन्द्र सिंह की बातचीत के कुछ अंश।

**Q** बीते चार दशक में उद्यमिता क्षेत्र में प्रगति को कैसे देखते हैं?

**A** बीते चार दशक में उद्यमिता क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। युवा आज उद्यम शुरू करने को और परिजन इसमें उसका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। बीते 8-9 सालों से जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आई है तब से नीतियों के जरिए उद्यमिता, स्वरोजगार, इनोवेशन, स्टार्टअप को काफी बढ़ावा मिला है। मुद्रा फंडिंग के तहत 8 साल में 23 लाख करोड़ का वितरण इसका प्रमाण है। केन्द्र के साथ कई राज्य सरकारों भी नीतियां बनाकर इसे बढ़ावा दे रही हैं। आज उद्यम शुरू करने के लिए पैसे की



डॉ.सुनील शुक्ला, महानिदेशक,  
ईडीआईआई

कमी नहीं है। मार्केट भी है। जरूरत नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने की है।

**Q** जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में भी उद्यमिता पर काम चल रहा है क्या योजना है?

**A** उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ईडीआईआई का लद्दाख में अपना केन्द्र शुरू करने और जम्मू

एवं कश्मीर एन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (जेकेईडीआई) की स्थापना में मददगार होने के बाद अब उसके साथ मिलकर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की तैयारी है। जम्मू एवं कश्मीर में माहौल काफी बदला है। ऐसे में वहां शिल्प, पर्यटन, कटरिंग, टूरिज्म मार्केटिंग के क्षेत्र में जबकि लद्दाख में पशुमिनी कारीगरों को ट्रेनिंग, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छे अवसर हैं। कोरोना महामारी के चलते ब्रेक लगी थी अब फिर से तेजी आई है। उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर भी संस्थान वहां के युवाओं को उद्यमिता और नवाचार की ट्रेनिंग देने की तैयारी है। कई अच्छी नीति वहां की सरकार ने बनाई हैं।

**Q** पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमिता को लेकर क्या स्थिति है?

**A** केन्द्र सरकार के साथ मिलकर संस्थान प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिसिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट (पीएम-डिवाइन) के तहत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों-असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा में युवाओं, महिलाओं को उद्यमिता के गुरु सिखाने पर बड़े पैमाने पर काम करने की तैयारी कर रहा है। ताकि इन राज्यों के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार मिल सके। 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए महिलाओं, युवाओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

**Q** दिव्यांगों, अनुसूचित जाति वर्ग को उद्यमिता बनाने पर क्या हो रहा है?

**A** दिव्यांगों को सिर्फ उपकरण देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें उनकी रुचि, क्षमता, हुनर के अनुरूप प्रशिक्षित कर एक उद्यमी के रूप में उभरने का प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे वे किसी पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर बनें और अन्य को भी रोजगार दें। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की इस सोच पर गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर ईडीआईआई ने काम शुरू किया जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से 50 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति आबादी वाले गांव चिन्हित कर वहां के युवाओं को उद्यमिता के पाठ पढ़ाने की तैयारी है। केन्द्र सरकार की मदद से भी इस पर काम हो रहा है।